

राष्ट्र की बात

लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक



www.rashtrakibaat.com



पेज नं० 5 भारतीय राष्ट्रगान के एपीक संस्करण ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

■ वर्ष : 20, अंक:12

■ लखनऊ, शुक्रवार, 30 अगस्त 2024

■ पृष्ठ : 8, ■ मूल्य 03:00 रु/-

आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को मिलता रहेगा लाभ

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। निजी अस्पताल मरीजों को इलाज देने से मना नहीं कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज न मुहैया कराने का निर्णय लिया था। कहा था कि आगामी 1 सितंबर से ये सुविधा निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होगी। अस्पतालों के इस फैसले का जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सज़ान लिया। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी अस्पतालों से कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की व्यवस्था जारी रखें। दरअसल, निजी अस्पतालों ने हाल में एक फैसला किया। इस फैसले में कहा गया है कि उन पर कई करोड़ रुपये का बकाया इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है, जो उन्हें नहीं चुकाया गया है। जिसकी वजह से अस्पतालों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की। साथ ही निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों में मरीजों को इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के तहत देते रहें। आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

मनरेगा में लाखों का फर्जी वाड़ा 5 साल से लग रही फर्जी हाजिरी

दिल्ली से मनरेगा में फावड़ा चला रहा मजदूर

लेखराम मौर्य
लखनऊ,। सरकार की नाक के नीचे राजधानी के विकासखंड माल की एक पंचायत में कागजों में मनरेगा योजना चल रही है। यहां 5 वर्ष से दर्जनों मजदूरों की फर्जी हाजिरी लग रही है जबकि उन्होंने आज तक मनरेगा का काम कहां चल रहा है इसका मौका तक नहीं देखा है यही नहीं एक मजदूर दिल्ली में रहकर गांव में मजदूरी भी कर रहा है फर्जी वाड़ा इस कदर किया गया है कि 15 अगस्त 26 जनवरी और दीपावली में भी यहां मनरेगा में काम बंद नहीं होता है। राजधानी के विकासखंड माल की ग्राम पंचायत बहिर में मनरेगा योजना के अंतर्गत जहां वास्तविक स्थिति में काम कराया गया है वहां 10 दिन 7 मजदूरों ने काम किया और कागजों में एक महीने से अधिक काम दिखाया गया है इसके अलावा जिन मजदूरों ने उस कच्चे संपर्क मार्ग में काम किया है उनकी उपस्थिति कहीं दूसरी जगह दिखाकर भुगतान किया जा रहा है जबकि उस सड़क में फर्जी भुगतान वाले लोगों की उपस्थिति दिखाई गई है यही नहीं कुछ संपर्क मार्ग कागजों में ही पहले भी बन चुके हैं और कुछ संपर्क मार्ग जिन पर काम दिखाया गया है वहां 2 साल पहले काम हुआ है और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है इन पर फर्जी हाजिरी लगाई गई है जिससे यहां लाखों का फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रामीणों

के अनुसार करीब दो माह पूर्व बरौकी से हरदोई सीमा की ओर कुछ दूरी तक काम होने के बाद पानी बरसने के कारण काम बंद हो गया था इस संपर्क मार्ग पर मात्र 10 दिन काम हुआ था उसके बाद बाकी रास्ता अधूरा पड़ा है जबकि इसमें एक महीने से अधिक काम दिखाया गया है मजदूरों ने बताया कि



इस संपर्क मार्ग में खूबराम, गजोधर, कमलेश, राम प्रसाद, रमदेई, कैलाश और एक अन्य व्यक्ति ने 10 दिन काम किया था जबकि दूसरी ओर इस संपर्क मार्ग में इनमें से कई मजदूरों की उपस्थिति नहीं दिखाई गई है इनकी उपस्थिति कहीं और दिखाई गई है जहां मौके पर काम ही नहीं हुआ है। इसी पंचायत के मजरे गुलाल खेड़ा निवासी कृपाश्याम जो होमगार्ड में नौकरी करते

हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 में इनकी भी मनरेगा में उपस्थिति दिखाई गई है इसके अलावा इनकी पत्नी ममता की उपस्थिति लगातार दर्द की जा रही है उनके लड़के अंकित और पुत्री प्राची का अलग अलग जॉब कार्ड बनाकर फर्जी उपस्थिति दिखाई गई है जबकि यह एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं

ग्रामीणों के अनुसार सुनील कुमार पत्नी के साथ एक साल से अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं फिर भी उनकी उपस्थिति मनरेगा में दिखाकर लगातार फर्जी भुगतान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इनके अलावा साहिल गाजी मोहम्मद अरमान जमीला आशुतोष और मोहम्मद शोएब सहित कई अन्य लोग भी जिनकी उपस्थिति फर्जी दर्ज की जा रही है जबकि यह लोग कभी मजदूरी करने नहीं जाते हैं यहां जिस तरह से सरकारी पद का दुरुपयोग कर गलत जॉब कार्ड बनाए गए हैं जिनके द्वारा फर्जी भुगतान किया गया है उसमें विकासखंड कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में यह नहीं देखा कि अविवाहित लड़की का जॉब कार्ड कैसे बना दिया गया और लगातार भुगतान करते रहे। सचिव सत्य प्रकाश का कहना है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा का कार्य चल रहा था परंतु प्रधान ने बताया कि 3 दिन से बंद है जबकि ग्रामीणों के अनुसार काफी दिनों से मनरेगा का कोई काम नहीं चल रहा है मनरेगा की साइट पर संजय के बाग से मोलहे की बाग तक मनरेगा का काम काम चलता हुआ दिखाया जा रहा है सचिव के अनुसार प्रधान ने बताया कि 3 दिन से काम बंद है जबकि अभिलेखों में काम चल रहा है। खंड विकास अधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया।

बिना मिस्त्री के ही हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर पर खर्च हो गए लाखों रुपए



लखनऊ, संवाददाता। कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की बाढ़ आ गई है इसीलिए पंचायतों में प्रधानों द्वारा ठेके पर काम कराए जा रहे हैं जिससे कमीशन लेने में आसानी हो जाती है। एक सप्ताह पूर्व जिस पंचायत में मनरेगा का फर्जीवाड़ा सामने आया था उसी पंचायत में अन्य मदों का अधिकांश पैसा पिछले 4 साल से हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर के नाम पर ही खर्च दिखाया गया है जबकि इतनी बड़ी पंचायत नहीं है कि सारा पैसा हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर पर ही खर्च कर दिया जाए। इसके बावजूद यहां

कई हैंड पाइप आज भी खराब पड़े हैं। एक सप्ताह पूर्व राजधानी के विकासखंड माल की ग्राम पंचायत बहिर में बिना काम के फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा योजना में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था जिसकी अभी तक जांच भी नहीं की गई है और अब अन्य मदों के पैसे से हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाने का मामला सामने आया है। इंटरनेट पर दर्ज अभिलेखों को देखने से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 227181 हैंड पाइप मरम्मत और 32000 रुपए रिबोर पर खर्च किए गए। इसी

तरह 2022-23 में 224 990 रिबोर 176280 हैंड पाइप मरम्मत पर खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2023,24 में 730580 रुपए हैंड पाइप मरम्मत और 65240 रिबोर पर खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024, 25 में 146970 हैंड पाइप मरम्मत और 89130 रुपए रिबोर पर खर्च किए गए। यहां खास बात यह है कि 2021 से अब तक किसी भी मिस्त्री को हैंड पाइप मरम्मत या रिबोर के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया जबकि मोहम्मद शोएब के नाम से हैंड पाइप मरम्मत, रिबोर, प्रशासनिक व्यय, सफाई कार्य शौचालय में लेबर और सैनिटाइजेशन के नाम पर भुगतान किया गया है इसके अलावा एक एजेंसी के नाम भी लेबर का 77590 रुपए भुगतान दिखाया गया है जबकि किसी एजेंसी को मजदूरों का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है। फर्जीवाड़े का हाल यह है कि रामरति ट्रेडर्स के नाम जेसीबी से सफाई के लिए 59500 और जेसीबी वर्क के लिए ही कृष्णा इंटरप्राइजेज के नाम 15000 का भुगतान किया गया है जबकि उसके पास कोई जेसीबी नहीं है। इस पंचायत में सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2021-22 में बनाया गया सार्वजनिक शौचालय आज तक अधूरा पड़ा है और केयरटेकर का भुगतान लगातार किया जा रहा है।

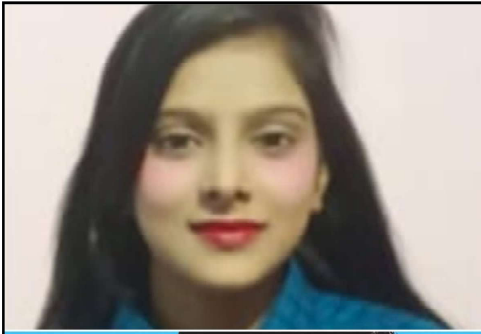
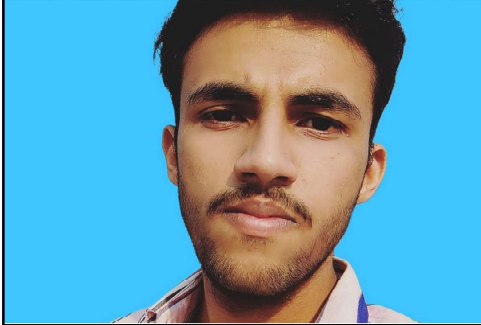
राज्य वित्त और 15 वें वित्त में एक ही परिवार को मिला काम



लखनऊ, संवाददाता। राजधानी के विकासखंड माल की दूसरी पंचायत जहां भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है क्योंकि यहां प्रशासनिक खर्च, मिट्टी पट्टाई, पेंटिंग, रिपेयरिंग, हैंड पाइप मिस्त्री, हैंड पाइप मरम्मत, कीटनाशक स्प्रे, रिपेयरिंग आदि का भुगतान मात्र तीन लोगों के नाम किया गया और मजदूरी का कार्य इस परिवार के पांच लोगों ने किया जिन्हें गांव के किसी व्यक्ति ने काम करते हुए भी नहीं देखा। दूसरों से मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड माल की ग्राम पंचायत रहटा में पंचायत भवन मरम्मत, नाली निर्माण, आंगनबाड़ी भवन मरम्मत के कार्य में जिन मजदूरों ने काम किया उनके नाम अभिषेक सिंह, बृजेश कुमार सिंह, अविनाश सिंह, शिवा सिंह, धर्मेन्द्र सिंह है। इसके अलावा जो भुगतान

किए गए हैं वह धर्मेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र ट्रेडर्स, शिवा ट्रेडर्स के नाम से लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। यहां भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हैंड पाइप रिपोर्ट का भुगतान एक भट्टे के नाम कर दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि यहां भ्रष्टाचार चरम पर है और विकासखंड कार्यालय में तैनात कर्मचारी और अधिकारी इस तरह अनजान बने हुए हैं जैसे गांव में प्रधान और सचिव जो कुछ कर रहे हैं उससे विकासखंड के अधिकारियों को कोई लेना-देना नहीं है इसीलिए जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है वहां के सचिव और प्रधान को बुलाकर विकास खंड कार्यालय में ही उस पर पर्दा डाल दिया जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में सब इतने डूबे हुए हैं कि उनको मौके पर जाकर देखने की फुर्सत नहीं है।

कुलाधिपति और कुलपति द्वारा हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिलना शिक्षकों के लिए गौरव की बात - तारा देवी प्रबंधक



बलराम मौर्य
अयोध्या स सपने वही देखते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता बस हौसलों से उड़ान होती है

अंक 1799/1900 ने विश्वविद्यालयीय परीक्षा वर्ष 2024 में प्राप्त किया है स कुलाधिपति स्वर्ण पदक हेतु लिस्ट में शामिल नाम क्रमांक संख्या 03 में है स

स उक्त पंक्तियाँ किसी कवि ने मेहनतकश लोगों के लिए कही हैं स माँ तिलेसरा देवी पी0जी0 कालेज भसडा टांडा अंबेडकरनगर मे अध्ययन करने वाले छात्र व छात्रा ने अपने गुरु और अपनी मेहनत से महाविद्यालय का नाम रोशन कर दिया है स बताते चले कि माँ तिलेसरा देवी पी0जी0कॉलेज से नीलेश पांडेय (बी0एड0 द्वितीय वर्ष सर्वाधिक अंक सैद्धांतिक 764/800, प्रायोगिक 396/400) कुलपति स्वर्ण पदक हेतु लिस्ट में शामिल क्रमांक संख्या 14 पर नीलेश पाण्डेय को शामिल किया गया है व शालू वर्मा एम0ए0 संस्कृत (सर्वाधिक

जिसके कारण इन दोनों लोगों को डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के 29वें दीक्षांत समारोह में क्रमशः कुलपति एवं कुलाधिपति जी द्वारा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जाएगा । माँ तिलेसरा पी0जी0 कालेज के प्रबंधक श्रीमती तारा देवी ने कहा कि हमारे महाविद्यालय के दो छात्रों का चयन कुलाधिपति और कुलपति द्वारा गोल्ड मेडल मिलना हमारे शिक्षकों के लिए बड़े ही सम्मान की बात है स ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इस महाविद्यालय के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना अभिभावकों के लिए भी अपने बच्चों के लिए गर्व की बात है स महाविद्यालय परिवार आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। प्राचार्य डॉ0 सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से महाविद्यालय में शिक्षकों और शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को पढ़ाने के प्रति गंभीरता है इसी का परिणाम दो बच्चों का चयन गोल्ड मेडल के लिए हुआ है स आने वाले दिनों में गोल्ड मेडल पाने वालों की संख्या में वृद्धि होगी ।

मोबाइल देखने से मासूम बच्चों की आंखों पर पड़ रहा बुरा प्रभाव



बच्चे अब पढ़ाई के लिए मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके साथ ही बच्चों में टीवी देखने की भी लत भी काफी बढ़ गई है। लेकिन मोबाइल और टीवी की लत की वजह से बच्चों में मायोपिया बीमारी की समस्या बढ़ रही है। कोरोना काल के दौरान देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से कई महीने तक सभी लोग घरों में कैद थे, जबकि उसके बाद से लंबे समय तक स्कूलों की पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड में हुई थी। जिसकी वजह बच्चे पढ़ाई के साथ ही गेम खेलने और मनोरंजन

के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे थे। बता दें कि मायोपिया बीमारी में बच्चों की नजदीक की दृष्टि तो सही रहती है, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में उन्हें दिक्कत होती है। मायोपिया होने पर बच्चे टीवी देखने के दौरान आंखों को मीचकर टीवी देखते हैं या आंखों फैलाकर अथवा सिकोड़कर टीवी देखते हैं तो यह मायोपिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों के माता-पिता को चाहिए कि वो बच्चों में इस प्रकार के लक्षण देखें तो तत्काल किसी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करके बच्चे की आंखों की जांच करवायें।

हिंदी के विकास में ही देश का विकास सनिहित - केशव प्रसाद मौर्य



आचार्य स्कंददास मौर्य
अयोध्या धाम स हिन्दी भाषा की लोक प्रियता को देखते हुए अयोध्या से प्रकाशित लोकप्रिय पत्रिका साहित्य सम्राट के नवीनतम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने किया, उन्होंने कहा कि मातृभाषा हिंदी हमारी अभिव्यक्ति के साथ-साथ भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की संवाहक भी है, हिंदी के विकास में ही देश का विकास सनिहित है, हम सभी का प्रयास होगा कि हिंदी शीघ्र भारत की राष्ट्रभाषा बने जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार संपूर्ण विश्व में हो सकेस हिंदी के समुन्यन में संस्थान के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री ने संस्थान तथा पत्रिका समूह के उज्जवल भविष्य की कामना की, उक्त अवसर पर हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री पत्रिका के संपादक डॉवसम्राट अशोक मौर्य, संस्थान के संरक्षक मंडल सदस्य व कप्तानगंज के पूर्व विधायक मा.सी.ए.

चंद्र प्रकाश शुक्ला व संस्थान के राष्ट्रीय सचिव डॉवभानु प्रताप उपाध्याय ने भारत सरकार से हिंदी को शीघ्र देश की राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की ।

लैटरल एंट्री से नौकरी करने वालों को हटाया जाए-मोहम्मद आमिर



आचार्य स्कंददास मौर्य
अयोध्या धाम । विंदु संप्रदाय की आचार्य पीठ चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल बड़ा स्थान में गौ, संत, परमार्थ सेवी श्रीमहंत बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री देवेन्द्र प्रसादाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता एवं पावन सानिध्य में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर

श्री कृष्ण लीला मंडली के कलाकारों द्वारा मनमोहक श्री कृष्ण जन्म की लीला का भव्य मंचन किया गया। कारागार में प्रगट हुए भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी द्वारा जमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुंचाने की दिव्य झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला मंचन का दर्शन करने

भक्तों की भीड़ दशरथ महल में जमा रही। मंदिर में 12 बजतेही घंटा, घड़ियाल, ढोल, मजीरा, नगाड़ा बजने लगा, शंख ध्वनि होने लगी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की., हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, की जयघोष से संपूर्ण दशरथ महल मंदिर प्रांगण गूंज उठा। भगवान की आरती उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर में सखियों द्वारा बधाई गीतों पर झूम झूम कर नृत्य किया जाने लगा बिंदुगद्याचार्य स्वामी श्री देवेन्द्र प्रसादाचार्य जी महाराज द्वारा संतो, नार्तको, सखियों को द्रव्य न्योछावर किया जाने लगा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पुनीत अवसर पर मंगल भवन पीठाधीश्वर कृपालु श्री राम भूषण दास जी महाराज, पंडित श्री विष्णु प्रसाद नायक शास्त्री जी उपस्थित रहे।

और आदिवासीयों को मिले आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों पर हमला

बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी. उनकी इस मांग के बाद

ही रद्द की गयी तो तार्किक तौर पर पूर्व में इस असंवैधानिक योजना



सैलून में बाल कटवा रहे युवक पर दबंगों का हमला

लखनऊ, । चिनहट थाना अंतर्गत एल्लिको तिराहे के पास सैलून में बाल कटवा रहे युवक पर दबंगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने सैलून में घुसकर युवक को लात-धूसों से पीटा और फिर धमकी देते हुए आरोपित वहां से भाग निकले। पीड़ित ने बताया कि कुछ वक्त पूर्व उनसे महानगर कोतवाली में दबंगों पर मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद से दबंग प्राथमिकी को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इंकार करने पर दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अश्विनी चतुर्वेदी के मुताबिक, डूडा कॉलोनी नन्दपुर निवासी विनोद कुमार एल्लिको तिराहे के पास बाल कटवाने गए थे। लिखित शिकायत में पीड़ित का आरोप है कि इसी बीच लक्की यादव और अक्शीर आ धमके। उन्होंने विनोद को ललकारते हुए हमला बोल दिया। पीड़ित को सैलून से घसीटकर पीटा। झगड़ा होते देखकर राहगीरों के बीच बचाव पर आरोपी गाली गलौज करते हुए भाग निकले। विनोद ने पुलिस को बताया कि वह कुछ वक्त पूर्व तक अकबरनगर में रहता था। उसी कॉलोनी में लक्की, अक्शीर भी रहते थे।

दूसरे दिन यानी 20 अगस्त को आपकी सरकार द्वारा लैटरल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन को आरक्षण का प्रावधान न होने का हवाला देते हुए वापस लेने का स्वागत योग्य काम किया गया, लेकिन सवाल यह है कि 2019 से अब तक जिन 63 लोगों की लैटरल एंट्री के जरिये नियुक्तियां हुई हैं उन्हें भी क्यों नहीं पद से हटाया गया? जब यह योजना गैर संवैधानिक पाए जाने के कारण

से नौकरी पाए लोगों की नियुक्ति भी स्वतः अवैध हो जाती है. इन 63 में से 6 लोग तो सरकार से मोटी तनख्वाह लेकर फिर से निजी सेक्टर में भाग चुके हैं। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर ने मांग की कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इन लोगों को पद से हटाएं और उन्हें दिये गए वेतन और अन्य भत्तों की तय समय सीमा में वसूली सुनिश्चित करें।

डिजिटल मीडिया नीति 2024 - आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर उम्रकैद तक की सजा-विज्ञापन का श्रेणीवार 8 लाख प्रतिमाह तक भुगतान की भी व्यवस्था

यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 मॉडल के अनुकरण का स्वतःसंज्ञान सभी राज्यों को लेना समय की मांग

गोंदिया — वैश्विक स्तरपर दुनियां का हर देश आज डिजिटल हो गया है, तो कुछ देश होने की राह पर हैं इस डिजिटलाइजेशन ने हमारे जीवन को अति आसान व सुलभ बना दिया है, महीनों का काम मिनटों में हो जाता है। बटन दबाते ही डीबीटी से हितधारकों के पास रुपया पहुंच जाता है। सात समंदर पास पर बैठे व्यक्ति से भी यूं सेकंडों में व्हाट्सएप कॉलिंग से फेस टू फेस बात की जा सकती है तो, डिजिटल मीडिया की तो बात ही कुछ और है। हर मोबाइल यूजर व्यक्ति को आज सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम युटुब सहित अनेकों प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, परंतु उनके पास वक्त बहुत कम हो गया है, याने आज डिजिटल युग में मानवीय जीव को 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। परंतु इस सरलीकरण और कनेक्टिविटी ने अनेक दोष भी उत्पन्न किए हैं जिसका सटीक उदाहरण तुरंत दंगों की गति पकड़ना, आज हम घरेलू रूप से बंगाल बिहार राजस्थान सहित एब्रॉड देशों में भी देखते हैं कि थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है और इंटरनेट को उन क्षेत्रों में बंद कर दिया जाता है, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग न कर सके, क्योंकि एक पोस्ट से माहौल विपरीत दिशा में पलट जाता है। ठीक उसी प्रकार आज अनेक अश्लील, अमद्र व आपत्तिजनक पोस्ट कुछ खुरापाती लोगों द्वारा डाले जाते हैं, जिससे राष्ट्र का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ जाता है वहीं कुछ ऐसे महान शिक्षाविद मानवीय जीव भी हैं जो व्हाट्सएप पोस्ट ऐसा करते हैं कि, सांप भी मरे और लाठी बिना टूटे, या हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, याने उस पोस्ट से अपने विरोधीपर टांटिंग भी हो जाए और कानूनी रूप से सेफ भी रहे। आज हम इस विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक अति हाई प्रोफाइल शिक्षाविद व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य हूं जिसमें दिनांक 28 अगस्त 2024 को देर शाम एक समिति के एक पक्ष ने तीन पोस्ट डाले तो इस समिति के दूसरे पक्ष ने भी काउंटर जवाब में शानदार तीन पोस्ट डालें जो बिल्कुल कानून के दायरे में थे, इसी वजह से मुझे प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 व प्रौद्योगिकी आचार संहिता (संशोधित) नियम 2023 की याद आई फिर मैंने देर रात्रि इसपर रिसर्च शुरू की और उत्तर प्रदेश डिजिटल नीति 2024 सहित सब की समरी बनाकर आर्टिकल तैयार किया।

चूंकि यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 में, आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर उम्र कैद तक की सजा व विज्ञापन का श्रेणीवार 8 प्रतिमाह तक भुगतान की भी योजना बनाई गई है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट पर लगाम व नकेल कसने व शासकीय योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी तथा यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 मॉडल के अनुकरण का स्वतःसंज्ञान सभी राज्यों को लेना समय की मांग है। साथियों बात अगर हम यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को समझने की करें तो, सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट वायरल होते रहते हैं, चाहे वो सही हों या गलत लेकिन, अब उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 को 27 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति में सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अमद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। अभी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है। अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अमद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड (संशोधित) 2023 जारी किए थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। पॉलिसी के अनुसार, यूपी सरकार की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में

सामग्री/टवीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और शेयर करने पर एजेंसियों/फर्मों को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति को मंजूरी मिलने से देश के अन्य हिस्सों और यहां तक घर्क विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विभाग ने सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर इनप्लुएंसर्स एजेंसियों/फर्मों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नीति में कहा गया है कि श्रेणी के अनुसार, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स/अकाउंट होल्डर्स/ऑपरेटरों को अधिकतम क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि नीति के अनुसार, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के आधार पर परिभाषित श्रेणी के अनुसार यूट्यूब पर

फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 4 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई है। साथियों बात अगर हम भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधित नियम 2023 की करें तो, नियमों की मुख्य विशेषताएं भारत में अधिसूचित सीमा से ऊपर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनको कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है जैसे अनुपालन के लिए कुछ कर्मियों की नियुक्ति करना, कुछ शर्तों के तहत अपने प्लेटफॉर्म पर

या संचारित करती हैं, और इसमें दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऑनलाइन बाजार, खोज इंजन और सोशल मीडिया साइटें शामिल हैं। ख, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) को किसी तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए मध्यस्थों को दायित्व से छूट प्रदान करने के लिए 2008 में संशोधित किया गया था। ख, इसके बाद, आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 को आईटी अधिनियम के तहत तैयार किया गया ताकि मध्यस्थों को ऐसी छूट का दावा करने के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया जा सके। ख, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को 2011 के नियमों को बदलने के लिए 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया था। ख, 2021 के नियमों के तहत प्रमुख परिवर्धन में कुछ सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए अतिरिक्त उचित परिश्रम की आवश्यकताएं और समाचार और समसामयिक मामलों के ऑनलाइन प्रकाशकों की सामग्री को विनियमित करने के लिए एक ढांचा और क्यूरेटेड ऑडियो-विजुअल सामग्री शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उल्लेख किया कि व्यापक चिंताओं के कारण ये बदलाव आवश्यक थे। (प) बाल पोर्नोग्राफी और यौन हिंसा को दर्शाने वाली सामग्री का प्रचलन, (पप) फर्जी खबरों का प्रसार, (पपप) सोशल मीडिया का दुरुपयोग, (पअ) ओटीटी प्लेटफार्मों और समाचार पोर्टलों सहित ऑनलाइन प्रकाशकों के मामले में सामग्री विनियमन, (अ) डिजिटल प्लेटफार्मों से पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, और (अप) डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के उपयोगकर्ताओं के अधिकार। 2011 के नियमों के तहत, आवश्यकताओं में शामिल हैं (प) सेवा समझौतों में, उन सामग्री की श्रेणियों को निर्दिष्ट करना जिन्हें उपयोगकर्ताओं को अपलोड या साझा करने की अनुमति नहीं है, (पप) न्यायालय या सरकारी आदेश प्राप्त करने के 36 घंटों के भीतर सामग्री को हटाना, (पपप) कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करना, (पअ) अवरुद्ध सामग्री और संबंधित रिकॉर्ड को 90 दिनों तक बनाए रखना, और (अ) उपयोगकर्ताओं और प्रभावित व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना, और एक शिकायत अधिकारी को नामित करना। 2021 के नियम इन आवश्यकताओं को बरकरार रखते हैं, जबकि (प) सामग्री की श्रेणियों को संशोधित करना जिन्हें उपयोगकर्ताओं को अपलोड या साझा करने की अनुमति नहीं है, और (पप) उपरोक्त आवश्यकताओं के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित करना। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि डिजिटल मीडिया नीति 2024 — आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर उम्र कैद तक की सजा—विज्ञापन का श्रेणीवार 8 लाख प्रतिमाह तक भुगतान की भी व्यवस्था। यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 मॉडल के अनुकरण का स्वतःसंज्ञान, सभी राज्यों को लेना समय की मांग। आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर लगाम नकेल कसने व शासकीय योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 मील का पत्थर साबित होगी।



वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट के लिए भुगतान क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा, सरकार ने अपने कार्यों और नीतियों के प्रचार के लिए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी भी लागू की है, इस पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इनप्लुएंसर को भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नीति के अंतर्गत इनप्लुएंसर्स को सूचना विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस पॉलिसी के तहत एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म के इनप्लुएंसर के लिए समान श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। जिन्हें उनके

सूचना के पहले स्रोत की पहचान करने में सक्षम बनाना और कुछ प्रकार की सामग्री की पहचान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना। नियमावली में समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री तथा संपादित दृश्य-श्रव्य सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा सामग्री के विनियमन के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। सभी मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना आवश्यक है। प्रकाशकों के लिए स्व-नियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया गया है। प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण ये नियम कुछ मामलों में अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों से परे जा सकते हैं, जैसे कि वे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन प्रकाशकों के विनियमन का प्रावधान करते हैं, और कुछ मध्यस्थों को सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान करने की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने के आधार बहुत व्यापक हैं और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मध्यस्थों के कब्जे में मौजूद सूचना के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए अनुरोधों के लिए कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है। जैसे कि वे मध्यस्थों के अपने प्लेटफॉर्म पर सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान सुनिश्चित करना, व्यक्तियों की गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मध्यस्थ ऐसी संस्थाएं हैं जो अन्य व्यक्तियों की ओर से डेटा संग्रहीत

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म

‘तिकड़म’ की स्पेशल स्क्रीनिंग लखनऊ में संपन्न



पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि के बीच एक पिता और उसके बच्चों के बीच के मार्मिक रिश्ते को

दर्शाती फिल्म शतिकड़मश्र जियोसिनेमा पर रिलीज होने के बाद से ही इन दिनों बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस फिल्म ने दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया है। फिल्म की सफलता और प्रभाव को देखते हुए, मेकर्स ने लखनऊ में स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। 29 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में आईएएस, आईपीएस अधिकारी समेत यूपी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस फिल्म का आनंद उठाया। ज्योति देशपांडे और पार्थ गज्जर, पूनम श्रॉफ, सवियो शेनॉय और श्वेता शर्मा आंचलिया द्वारा निर्मित फिल्म शतिकड़मश्र के इस स्पेशल स्क्रीनिंग में अभिनेता अमित सियाल और निर्देशक विवेक आंचलिया भी मौजूद थे। प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

सम्पादकीय

दुश्वारियों का रास्ता

अमेरिका आदि देशों में सुनहरे सब्जबाग दिखा मोटी रकम वसूलकर युवाओं को जानलेवा अंधी गलियों में धकेलने वाले एजेंटों पर समय रहते कार्रवाई न होना हमारे शासन-प्रशासन की विफलता ही कही जाएगी। मोटी कमाई और चमकीले सपनों का सम्मोहन युवाओं की सोचने-समझने की शक्ति को ही कुंद कर देता है कि वे ऐसा करके अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल, डंकी रूट अमेरिका आदि देशों में जाने का एक ऐसा अवैध रास्ता है, जिसमें सीमा नियंत्रण के प्रावधानों को धत्ता बताकर एक लंबी व चक्करदार यात्रा के माध्यम से दूसरे देश ले जाया जाता है। एक दशक से जारी यह गोरखधंधा वर्ष 2023 में तब उजागर हुआ था जब वर्ष 2023 में फ्रांस ने मानव तस्करी के संदेह में दुबई से निकारागुआ जा रहे तीन से अधिक यात्रियों वाले एक चॉर्टर विमान को रोककर उसमें सवार अधिकांश भारतीयों को वापस भारत लौटा दिया था। हाल ही में पंजाब में समाना के चार युवाओं की दर्दनाक कहानी उजागर हुई है, जिन्हें एजेंटों ने मोटी रकम वसूलकर जानलेवा हालातों में धकेल दिया। उनसे दो चरणों में करीब ढाई करोड़ रुपये वसूले गये और घातक परिस्थितियों में धकेल दिया गया। कई दिन जंगलों में उन्हें भूखा रहना पड़ा। फोन व जूते छीन लेने से उन्हें नंगे पैरों पैदल चलना पड़ा। पहले भारतीय एजेंट को प्रति व्यक्ति पैंतीस लाख देकर वे स्पेन पहुंचे, जहां उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। फिर वहां से प्रत्येक युवक ने पच्चीस लाख रुपये चुकाकर अमेरिका जाने की दुर्गम राह पकड़ी। अब इन पीड़ित युवाओं ने हर पंजाबी से अपील की है कि वे कभी भी पश्चिम जाने के लिये अवैध रास्ते को न चुनें। वे खुद को भाग्यवान मानते हैं इस खतरनाक रास्ते में लुटने-पिटने और भूखे रहने के बाद किसी तरह अमेरिका पहुंचे हैं। दरअसल, उनकी बदहाली की वजह वो भ्रष्ट व बेईमान ट्रैवल एजेंट था, जिसने उन्हें मोटी रकम लेकर अमेरिका में कार्य वीजा दिलाने का झांसा दिया था। निस्संदेह, युवाओं का धोखेबाज एजेंटों के जाल में फंसना हमारे तंत्र की विफलता ही है। यदि ऐसे एजेंट कानून व्यवस्था के शिकंजे में फंस गये होते तो युवा ठगी के शिकार न बनते। आखिर हम अपने युवाओं को देश में सम्मानजनक रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वहीं युवा भी धैर्य व कठिन परिश्रम के बजाय रातोंरात अमीर बनने के सपने सजोने लगते हैं। आखिर क्या वजह है कि मां-बाप जमीन बेचकर व अपने गहने-मकान गिरवी रखकर बच्चों को विदेश भेजने को आतुर हैं? यह जानते हुए कि आये दिन तमाम युवा फर्जी एजेंटों के जाल में फंसकर अपना सबकुछ गवांकर देश लौटते हैं। पिछले दिनों दलालों ने देश के युवाओं को सुनहरे सपने दिखाकर युद्धरत रूस की फौज में भर्ती करवा दिया। कई युवाओं के युद्ध में मरने की खबरें भी आईं। आखिर सुनहरे सपनों की चकाचौंध में हमारे युवा दलालों के हाथों के खिलौने क्यों बन रहे हैं? अमेरिका जाने के सम्मोहन में अपने जीवन को इस तरह जोखिम में डालना क्या उचित है? भारत अन्य देशों के साथ मिलकर युवाओं को धोखे से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिये क्या कर रहा है? निस्संदेह, विभिन्न महाद्वीपों के राष्ट्रों को शामिल किए बिना दलाली-ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का खातमा संभव नहीं है। एशिया, यूरोप व मध्य अमेरिका तक दलालों के जाल बिछे हैं। अपना कमीशन लेकर वे युवाओं को आगे धकेलते हैं। ऐसे मामले उजागर होने के तुरंत बाद कुछ गिरफ्तारियां इस बड़े संकट का समाधान नहीं है। आपराधिक कृत्यों में लिप्त एजेंट कुछ समय के लिये तो चुप बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद वे अपने नापाक खेल में फिर सक्रिय हो जाते हैं। वैसे वे युवा भी कम दोषी नहीं हैं जो वास्तविक स्थिति को जाने बिना शॉर्टकट रास्ते के लिये दलालों को पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल, विदेश जाने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक चैनल को दरकिनार करने के खतरों के बारे में भी बताना चाहिए। इसके लिये उन्हें सचेत करने के मकसद से जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इस लड़ाई में सभी हितधारक भी जिम्मेदार भूमिका निभाएं।

आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता के रूप में उमरीं सुनीता केजरीवाल

कल्याणी शंकर

किसने सोचा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में स्वीकार्य नेता के रूप में उभरेगी! इस साल 21 मार्च से शराब घोटाले में अपने पति के जेल जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह अपने पति और पार्टी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गयी हैं। हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों ने उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने के बाद वह पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगी या नहीं। राजनीतिक परिवारों की महिलाएं अक्सर अपने रिश्तेदारों के विकल्प के रूप में राजनीति में प्रवेश करती हैं। एक सफल उदाहरण सोनिया गांधी हैं। वह सिंहासन के पीछे की शक्ति थीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने 2000 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। लालू को एक घोटाले में कथित संलिप्तता और अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। राबड़ी देवी केवल एक रबर स्टाम्प थीं, जबकि उनके पति वास्तविक मुख्यमंत्री थे।हो सकता है कि वह राजनीति में नौसिखिया हों, लेकिन सुनीता अपने साथ बहुत अनुभव और ठोस पेशेवर पृष्ठभूमि लेकर आई हैं। आयकर विभाग में उनका 22 साल का कार्यकाल, जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में आयकरआयुक्त के रूप में समाप्त हुआ, उनकी योग्यता को दर्शाता है। सुनीता ने अपने पति केजरीवाल का समर्थन किया, यहां तक कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान भी जब वे एक राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता बन गये। केजरीवाल ने खुद को एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में पेश किया और चुनावों के दौरान सुनीता के साथ प्रचार किया। आम आदमी पार्टी में सुनीता की बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से केजरीवाल के कारावास के बाद, उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। केजरीवाल भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल के इस्तीफा देने पर उनके उत्तराधिकारी बनने की अटकलें लगाई

जा रही हैं। दूसरी बात, सुनीता का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। वह ऐसे समय में आई हैं, जब आम आदमी पार्टी संकट से जूझ रही है। हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में जनवरी 2025 में चुनाव होने हैं। कई वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पार्टी की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। केंद्र ने उन्हें लंबे समय तक पद पर बने रहने दिया और संवैधानिक विफलता के आधार पर उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। केजरीवाल के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में सुनीता की भूमिका खत्म हो जायेगी। सिसोदिया को पिछले साल

आधिकारिक पद नहीं है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार किया और अभी हरियाणा में प्रचार शुरू किया है। वह मोदी सरकार और भाजपा पर तीखे प्रहार कर रही हैं। उनका बचाव यह था कि कुछ राजनीतिक ताकतें उनके पति को बदनाम करने में शामिल हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुनीता की बढ़ती भागीदारी और स्वीकार्यता को स्वीकार किया है। हाल ही में रामलीला मैदान में हुई रैली में वह सोनिया गांधी के साथ प्रमुख स्थान पर बैठी थीं। सुनीता ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए श्केजरीवाल की पांच गारंटीश के साथ अपना अभियान शुरू किया है। इनमें मुफ्त बिजली, चिकित्सा, शिक्षा,



आबकारी नीति मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। आप सांसद संजय सिंह का दावा है कि केजरीवाल के संदेशवाहक के रूप में सुनीता की भूमिका बढ़ रही है। फिर भी, केजरीवाल का कहना है कि सुनीता की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। तीसरा, हालांकि सुनीता को कामचलाऊ विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव के कारण उन्हें किनारे करना चुनौतीपूर्ण है। केजरीवाल के वापस आने पर भी पार्टी में सुनीता की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। चौथा, पार्टी नेतृत्व के संकट का सामना कर रही है। आगामी हरियाणा और दिल्ली चुनावों के मद्देनजर आप को एक विश्वसनीय नेता और एक अच्छे प्रचारक की जरूरत है। सुनीता एक अच्छी प्रचारक के रूप में उभरी हैं। वह महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं। वह एक अच्छी वक्ता भी हैं। पांचवां, आप के सदस्यों ने सुनीता को कड़ी के रूप में स्वीकार किया है, हालांकि सुनीता के पास आप में कोई

महिलाओं के लिए 1,000 डॉलर मासिक सहायता और युवाओं को रोजगार शामिल हैं। उन्होंने आप सरकार की पहल की सराहना की और लोगों से आप को वोट देने का आग्रह किया। सुनीता के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। केजरीवाल की राजनीतिक सफलता के बावजूद, सुनीता की राजनीतिक परीक्षा नहीं हुई है। वह पार्टी को बरकरार रख पाती हैं या नहीं, यह अभी तय नहीं हो पाया है। उनका सीमित उद्देश्य जेल से केजरीवाल का संदेश पहुंचाना और आगामी चुनावों के लिए प्रचार करना है।सुनीता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी अन्य पार्टियों से बातचीत कर रही हैं और उन्होंने विपक्ष के शीर्ष नेताओं तक पहुंच बना ली है। उम्मीदवारों के और गठबंधन बनाने की उनकी रणनीति आम आदमी पार्टी के भविष्य के गठबंधनों पर निर्भर करती है। दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आप के लिए सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण है।

राष्ट्रपति का भय और निराशा

सर्वमित्रा सुरजन

देश की राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बहुत निराश और भयभीत हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा पर अपना भय और निराशा दोनों जाहिर करते हुए कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ाईत नहीं, बस अब बहुत हुआ। राष्ट्रपति का यह बयान साफ तौर पर मोदी सरकार की नाकामी को दर्शा रहा है। बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ जैसी बातें करने वाली सरकार के शासन का सच क्या यह है कि भारत इतना असुरक्षित देश बन चुका है, जहां राष्ट्रपति को भी डर लगने लगा है और निराशा होने लगी है। माननीय राष्ट्रपति महोदया से यह पूछा जाना चाहिए कि अगर आप अपने डर का इजहार इस तरह करेंगी, तो इस देश की आम लड़कियां कहां जाएंगी और उनके मां-बाप, परिजन, किसके पास जाकर अपनी निराशा को जाहिर करेंगे। काश, राष्ट्रपति ने इस भय और निराशा को तब जाहिर किया होता, जब मणिपुर में

कुकी-जोमी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र जुलूस निकालकर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से छलनी कर दिया गया था। इस मामले की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दी। कई मंचों से भारत के सभ्य समाज के इस घिनौने चेहरे पर चर्चा हुई। देश के भीतर अनेक तबकों ने उनसे आग्रह किया था कि वे इस मामले पर कुछ तो कहें, क्योंकि आपकी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने तो मुंह पर ताला ही लगा लिया था। हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी नेता ने राष्ट्रपति मुर्मू को बहुत दुखी मन से पत्र भी लिखा था। श्री सोरेन ने 22 जुलाई 2023 को लिखे पत्र में आपसे कहा था कि श्रृंखरा के सामने चुप्पी एक भयानक अपराध है, इसलिए मैं आज मणिपुर में हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको पत्र लिखने के लिए मजबूर हूँ, श्रमणिपुर और भारत के सामने आने वाले संकट के इस सबसे कठिन समय में हम आपको आशा और प्रेरणा

के अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं जो इस कठिन समय में मणिपुर के लोगों और भारत के सभी नागरिकों को रोशनी दिखा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदया तब भी चुप रहीं। कुछ और नेताओं ने भी उनसे मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बोलने का नाकाम आग्रह किया था। इसके बाद जब महिला पहलवान यौन उत्पीड़न के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने उतरीं और राजनीति के अखाड़े में उन्हें मात देने की कोशिशें चलती रहीं, तब भी राष्ट्रपति की तरफ ही निगाहें टिकी थीं कि कम से कम इस मामले में वे कुछ कहेंगी। लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। फिर अभी ऐसा क्या हो गया है कि उनको भी डर और निराशा का अहसास होने लगा है। दरअसल कोलकाता में आर जी कर सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का जो घघन्य अपराध हुआ, उस पर इस समय देश भर में रोष की लहर उठी है। यह लहर वैसी ही है, जैसे 12 साल पहले दिल्ली निर्भया मामले के बाद तत्कालीन यूपीए

सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ समाज में नाराजगी देखी जा रही थी। तब समाज के बहुसंख्यक वर्ग की नाराजगी को भाजपा ने कांग्रेस सरकार को अपदस्थ करने का जरिया बनाया था। हालांकि निर्भया के इलाज की समुचित व्यवस्था से लेकर, उसके परिजनों की मदद और दोषियों पर कार्रवाई तक कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं हटी। न ही तत्कालीन प्रधानमंत्री डामनमोहन सिंह ने इस मामले में चुप्पी साधी या लोगों की नाराजगी का दमन किया। इसके बाद भी समाज के बड़े वर्ग को कांग्रेस की नाकामी नजर आई, भाजपा की चालाकी नहीं दिखी और नतीजा यह हुआ कि 2014 में यूपीए सत्ता से हट गई और नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब एक बार फिर वही खेल भाजपा खेल रही है, लेकिन इस बार खेल का मैदान प.बंगाल बना हुआ है। प.बंगाल की घटना को भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा और इंसाफ से बड़ा मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया है। भाजपा के 11

सालों के शासनकाल में कठुआ, हाथरस, उन्नाव, मणिपुर, उत्तराखंड, बदलापुर जैसी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो चर्चा में आईं, वहीं हजारों मामले ऐसे भी हुए हैं, जिनका कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया है। 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में हर 16 मिनट में एक बलात्कार की घटना हो रही है। यानी लड़कियों, महिलाओं के लिए वाकई भय का माहौल है। इसी माहौल में बलिकस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहाई और स्वागत का काम भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दोषियों को फिर से जेल में भेजा गया। मगर इस माहौल में जब गैरभाजपा शासित राज्य प.बंगाल का नाम आया, तब राष्ट्रपति महोदया अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, किसी भी सभ्य समाज में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दी जा सकती। समाज को भी ईमानदार, निष्पक्ष और आत्मनिरीक्षण होना चाहिए।



भारतीय राष्ट्रगान के एपीक संस्करण ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया



लखनऊ रु ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज के द्वारा एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कोलकाता स्थित सांस्कृतिक कार्यकर्ता संदीप भूतोरिया के साथ तैयार किए गए भारतीय राष्ट्रगान के एक महाकाव्य संस्करण ने गायक मंडली की विशेषता वाले सबसे बड़े गायन पाठ के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। जिसमें ओडिशा के लगभग 14,000 आदिवासी बच्चों के गायक मंडल ने एक साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक साथ इसका प्रदर्शन किया। इस वीडियो में भारत के जीवित संगीत दिग्गज – पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, अमन और अयान अली बंगश, राहुल शर्मा, जयंती कुमारेण, शेख और कलेशबी महबूब, गिरिधर उडुपा और यूके के रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के सदस्य भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रभा खेतान फाउंडेशन के ट्रस्टी संदीप भूतोरिया जो विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं ने कहा, प्यह परियोजना भारत की विविधता में

एकता का सच्चा उत्सव है, इसके साथ ही यह संगीत के क्षेत्र में सहयोग और सांस्कृतिक जगत में प्रतिनिधित्व के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओडिशा के हजारों बच्चों के साथ ऐसे दिग्गज कलाकारों के सहयोग से मिली उपलब्धि, पूरी दुनिया को हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत के बारे में एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण संदेश देती है। इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। रिकी केज ने कहा, प्यह परियोजना संगीत की शक्ति का एक प्रमाण है, जो लोगों को एक साथ लाता है। यह हमारे विविध विरासत का उत्सव और भारत की भावना को सम्मानित करता है। हम ने जो हासिल किया है, उस पर मुझे अत्यंत गर्व है, 14,000 बच्चों ने भारत का एक मानव मानचित्र बनाया और हिंदी और अंग्रेजी में 'भारत' शब्द का निर्माण किया, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसके युवा की असीम संभावनाओं का एक शक्तिशाली दृश्य प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रगान के इस संस्करण को यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों पर जारी किया

गया है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार रिकी केज ने भारतीय राष्ट्रगान की ऐतिहासिक संस्करण को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करके एक बार फिर संगीत की उत्कृष्टता का स्तर ऊंचा उठाया है। 2023 में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के बाद, जहां उन्होंने लंदन के एब्बे रोड स्टूडियो में भारतीय राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए अब तक के सबसे बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा (100-पीस रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा, यूके) का संचालन किया रिकॉर्डिंग 14 अगस्त को, भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, समी स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर जारी की गई थी, यह केवल एक संगीत उपलब्धि नहीं है बल्कि एकता और विविधता का प्रतीक है जो राष्ट्र को परिभाषित करता है। कुल मिलाकर, राष्ट्रगान की यह महाकाव्य संस्करण की प्रस्तुति न केवल संगीत की दुनिया में एक तकनीकी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत करती है। यह भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं के पार संगीत की एकजुट शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है।

समय लिख रहा है भारत के पाषाण युग में अस्त होने की दास्तां! - मंजुल भारद्वाज

यह समय मर्यादाओं के तार तार होने का है
यह समय हर पल शर्मसार होने का है
यह समय झूठे के राज का है
यह समय अर्धसत्य के शोर का है
यह समय सत्य की चीखों का है
पर उसे सुनने वाला कोई नहीं है
यह समय न्याय की अवधारणा को बुलडोजर से रौंदने का है !
यह समय अपने सामने अपना सब कुछ लुटा
धर्म और जात से गौरावित होने के भ्रम का है !
यह समय हत्याओं को सत्ता पर बिठा
अपराध रोकने की दिव्य मूर्खता का है !
यह समय विविधता, भाईचारे, सद्भाव को जलाकर
अखंड झूठ की भस्म लपेटकर मोक्ष प्राप्ति का है !
यह समय सौंदर्य को नष्ट कर
कुरूप और वीभत्स होने का है!
यह समय अपने ही मवाद में लिपटकर
अमृतकाल में जीने का है !
यह समय प्रेम को द्वेष से भस्म कर
नफरत में जलने का है !
यह समय लिख रहा है इतिहास
कैसे भारत के लोगों ने झूठे गर्व के लिए
अपने आपको तबाह कर लिया !
कैसे भारत के लोग झूठ से लड़ नहीं पाए
कैसे भारत के लोगों ने सत्य को सूली चढ़ाया
झूठे तानाशाह को लोकतंत्र की गद्दी पर बिठाया
और अस्मिता, न्याय, शांति, सद्भाव को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारा और जिंदा जला दिया !
यह समय लिख रहा है भारत का इतिहास
कैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से
हासिल हुई आजादी को
भारत के लोगों ने लुटा दिया !
यह समय लिख रहा है इतिहास
कैसे भारत में 3 महीने, 3 साल से लेकर 80 साल की
बच्चियों, औरतों, महिलाओं के गोशत को
सरे आम भेड़ियों ने नोचा
और लोगों द्वारा चुनी गई सत्ता ने
भेड़ियों का सम्मान किया !
समय लिख रहा है
भारत के पाषाण युग में
अस्त होने की दास्तां!

कर्मचारी ना होकर दिहाड़ी मजदूर है..? -अमिताभ सिन्हा



लखनऊ. उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के प्रांतीय महामंत्री सुहेल आबिद की अध्यक्षता में लेसा, रेजीडेंसी, लखनऊ में एक बैठक का आयोजन किया गया। पुरानी पेंशन को ना अंगीकार किया.. नियमित कर्मचारी, कर्मचारी ना होकर दिहाड़ी मजदूर है..? इस बैठक में गुफरान वारसी, सागर शर्मा, असीम श्रीवास्तव वैभव अरथाना प्रदीप वर्मा, दीपेंद्र कुमार अजय कनौजिया शोएब स्पीड राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे। सभी कर्मचारियों ने संगठन के सामने पुरानी पेंशन को ना अंगीकार किया जाने, विभागीय कर्मचारियों के यहां मीटर लगवाने, शासन की अनुरूपता में कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को ना अंगीकार किया जाने जैसे कई विषम ज्वलंत मुद्दों को संगठन के सामने रखा जिसे संगठन के प्रांतीय महामंत्री सुहेल आबिद्री ने शीघ्र अति शीघ्र निपटने का आश्वासन दिया। उप महामंत्री अमिताभ सिन्हा ने कहा कि सन 2000 के बाद भर्ती हुए कार्मिकों की ना तो पेंशन है और ना ही

उन्हें रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा एल एम बी 10 की सुविधा नहीं मिलेगी जो की अत्यंत ही शोचनीय विषय क्या 2000 के बाद भर्ती हुए नियमित कर्मचारी, कर्मचारी ना होकर दिहाड़ी मजदूर है..?

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु समिति की मासिक बैठक हुई सम्पन्न

प्रकाश शुक्ला
उन्नाव। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु समिति की मासिक बैठक सम्पन्न हुई। इस मौके पर उद्यमियों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष मैसर्स कैलिको इम्पैक्स में चोरी की घटना, एलाइड लैडर्स फिनीशर्स प्रा0लि0 द्वारा अतिक्रमण, औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत ट्रिपिंग, प्रॉपर ड्रेनेज, नाला-नालियों की साफ-सफाई, क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्पीड ब्रेकर, सिंगरोसी रोड पर जल निकासी की समस्या, दही चौकी व बन्थर औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के आवागमन हेतु ई-बसों के संचालन



की मांग, औद्योगिक भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने आदि समस्याएं रखी गयी। समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित

अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उद्यमियों की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व घालमेल पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या को लेकर डीएम ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया कि औद्योगिक फीडर से लगे गोंवों की लाईनों को अलग करते हुए उद्योगों को निर्बाध विद्युत सप्लाई उपलब्ध करायी जाए। साथ ही जर्जर विद्युत लाइनों व स्ट्रीट लाइटों को समय से सही कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मिणा, उपायुक्त उद्योग सुरेन्द्र कुमार, एआईजी स्टाम्प कंचन मिश्रा, एलडीएम सुनील वर्मा सहित समस्त उद्यमी व सम्बन्धित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

प्रेस क्लब प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्नाव का चुनाव हुआ संपन्न

उन्नाव। प्रेस क्लब प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्नाव के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सूची इस प्रकार है। अध्यक्ष पद पर धर्मेन्द्र मिश्रा, महामंत्री पद पर भानू सिंह चंदेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नसीर खान, उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद आमिर व अनुराग त्रिवेदी और कोषाध्यक्ष पद सलमान शफीक विजयी हुए। समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रकाश शुक्ला समाचार सम्पादक राष्ट्र की बात समाचार पत्र जीत की ओर हार्दिक बधाइयाँ।



केजीएमयू में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग का पहला स्थापना दिवस



लखनऊ। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में इलाज की व्यवस्था में तेजी से सुधार किए जा रहे हैं। आयुष्मान, असाध्य, सीएम-पीएम फंड से मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं ताकि मरीजों को दूसरे राज्यों की तरफ रुख न करना पड़े। संसाधन बढ़ाने में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये कहना है, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। केजीएमयू के ब्राउन हॉल में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के पहले स्थापना दिवस समारोह में गुरुवार को ब्रजेश पाठक ने कहा कि रिसर्च की दिशा में हमें और काम करने की जरूरत है। मरीजों की देखभाल व इलाज के लिए संसाधन में इजाफा करें। उपकरण खरीदे जाएंगे। मेडिकल पढ़ाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि केजीएमयू नए विभाग खोलने और मशीन का प्रस्ताव सरकार को भेजे, जिसे जल्द से जल्द मंजूरी दी जाएगी। न्यूक्लियर

मेडिसिन विभाग ने एक साल में शानदार काम किया है। विभाग में न्यूक्लीयर मेडिसिन से जुड़ी और भी जांचें शुरू करें। डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में गामा नाइफ की सुविधा मरीजों को मिलेगी। लोहिया संस्थान में गामा नाइफ मशीन स्थापित की जाएगी। इसके लिए बजट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि केजीएमयू में मरीजों का काफी दबाव है। डॉक्टर-कर्मचारी पूरी लगन से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मरीजों का भरोसा केजीएमयू के डॉक्टरों पर है। इलाज के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूक्लीयर मेडिसिन विभाग की अध्यक्ष डॉ. कीर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि एक साल के दौरान 2000 से ज्यादा पैट स्कैन हो चुके हैं। पैट स्कैन से शरीर में फैंले कैंसर का पता लगाने में मदद मिल रही है। इससे सटीक इलाज करने में मदद मिलती है। डॉ. प्रकाश सिंह ने कहा कि न्यूक्लीयर मेडिसिन विभाग को जल्द ही विस्तार दिया जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बने दूजी और थ्रीजी मीटर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सभी बिजली कंपनियों में लगभग 12 लाख पुरानी तकनीकी के 2जी, 3जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए उत्पीड़न मीटर साबित हो रहे हैं। लगभग 4 से 5 साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल साबित हुआ। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की उदासीनता का खामियाजा प्रदेश का विद्युत उपभोक्ता भुगत रहा। इसके विरोध में आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक जनहित प्रतिवेदन दाखिल किया। प्रत्यावेदन में लेसा का उदाहरण देते हुए यह मांग उठाई की राजधानी लखनऊ सहित इलाहाबाद मथुरा बरेली अलीगढ़ आगरा मेरठ नोएडा गाजियाबाद सहित अन्य जनपदों में जो 12 लाख स्मार्ट

मीटर लगाए गए हैं वह पूरी तरह ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहे हैं। कहने को स्मार्ट मीटर है लेकिन वह उत्पीड़न मीटर साबित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में यदि कोई भी स्मार्ट मीटर विद्युत उपभोक्ता



जिसका बकाया पर बिजली कनेक्शन कट जाता है। जब वह बकाया जमा करके अपना कनेक्शन पुनः जुड़वाना चाहता है तो आनेको मामलों में 8 से 10

घंटे तक उसका बिजली कनेक्शन जुड़ी नहीं पाता। उपभोक्ता पसीने बहा देता है बिजली अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते तब कहीं उसका बिजली कनेक्शन जुड़ता है। इसी प्रकार कभी

बारिश में बिजली चमकी तो मीटर बंद हो जाता है। कभी सप्लाई बंद कर देता है। लंबे समय से उपभोक्ता परिषद इसकी लड़ाई लड़ रहा है जिसकी

एसटीएफ जांच तक हुई लेकिन किसी भी दोषी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई और ना ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड पर कोई वैधानिक कार्यवाही की गई। उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल जनहित प्रत्यावेदन को विद्युत नियामक आयोग ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद को आश्वासन दिया कि यह बहुत गंभीर मामला है विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं होने देगा। पूरे मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग की वर्तमान में जो लगभग 27000 करोड़ के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के यहां लगाए जा रहे हैं। सभी बिजली कंपनियों लगभग 45000 मीटर उपभोक्ताओं के घर में लग गए वह अभी आज तक बिलिंग सर्वर से नहीं जुड़े हैं।

नगर आयुक्त व नगर स्वास्थ्य अधिकारी सहित पार्षदों की मौजूदगी में अभियान

लखनऊ,। नगर आयुक्त के आदेशानुसार नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी. के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में एवं मा. पार्षदगणों की उपस्थिति में नगर के अंतर्गत संचारी रोगों जैसे डेंगू व मलेरिया इत्यादि से बचाव एवं इनकी व्यापक रोकथाम के उद्देश्य से लगातार सघन अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों को अमल में लाया है रहा है जिसके लिए नगर निगम के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन नियमित रूप से योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज

नगर आयुक्त महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों एवं मा. पार्षदों के साथ नगर के चार प्रमुख वार्डों— जनकीपुराम प्रथम वार्ड, जनकीपुराम द्वितीय वार्ड, जनकीपुराम तृतीय वार्ड, भारतेंदु हरीश चंद्र वार्ड का निरीक्षण कर वृहद अभियान चलाकर सघन गतिविधियों को सुनिश्चित कराया गया। आज समस्त चारों वार्ड में अभियान चलाते हुए संचारी रोगों से बचाव के लिए टीमों को बनाकर क्षेत्रान्तर्गत मौजूद समस्त बड़े व छोटे नाले नालियों में, यहां मौजूद घरों में एन्टी-लार्वा का छिड़काव कराते हुए

फॉगिंग कराई गई। इसके अतिरिक्त बड़े नाले नालियों की सफाई भी वृहद रूप से कराई गई। साथ ही नगर आयुक्त महोदय द्वारा समस्त कर्मचारियों को प्रतिदिन नियमित रूप से टीमें बनाकर साफ सफाई इत्यादि कार्यों को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। स्थानीय लोगों को डेंगू व मलेरिया जैसे घातक संचारी रोगों की जानकारी देते हुए इनसे बचाव के तौर तरीकों इत्यादि के विषय में जागरूक भी किया गया। लोगों को क्या करें और क्या न करें इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।



भाजपा के प्रति अपना नजरिया बदले मुसलमान : मुख्तार अब्बास

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति अपने नजरिये में बदलाव लाने की अपील की। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की भाजपा सदस्यता अभियान की प्रांतीय कार्यशाला के सम्बोधन में नकवी ने गुरुवार को कहा कि दशकों से चले आ रहे मुसलमानों के भाजपा हराओ रिवाज को भाजपा जिताओ मिजाज में बदलने के लिए हमें समाज के भय-भ्रम को भरोसे में बदलने के लिए भरसक प्रयास करना होगा, जब भाजपा किसी के विकास में कमी नहीं करती तो उसे वोट में कंजूसी नाजायज है। नकवी ने कहा कि विपक्षी दलों का सेक्युलर सिंडिकेट मुसलमानों को अपने वोटों की जागीरदारी समझ बैठा है जिससे मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा "सामन्ती सुल्तानों के तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट के दुष्प्रचार से पैदा भय-भ्रम के चलते एक राष्ट्रीय-राष्ट्रवादी राजनैतिक दल के साथ अस्पृश्यता और असहिष्णुता के रवैये को भरोसे में बदलना ही वक्त की मांग है। कुछ सियासी सामन्ती सूबेदारों के संविधान, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और अल्पसंख्यकों पर खघरे के भय-भ्रम और भौकाल से देश के अल्पसंख्यकों को प्रगति की राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग करने की सोंच और साजिश से सावधान होने का यही समय है सही समय है। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी-योगी ने तुष्टीकरण के सियासी छल को सशक्तिकरण के समावेशी बल से ध्वस्त कर समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की प्राथमिकता से विकास और विश्वास का पुख्ता माहौल और



वैश्विक स्तर पर भारत की धाक-धमक को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि जो नेता लोकतंत्र के मंदिर में मत्था टेक संविधान को सीने से लगाकर सुशासन के समावेशी सफर को आगे बढ़ा रहे हों उन पर संविधान विरोधी का आरोप झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर प्रहार से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साम्प्रदायिक, समाज तोड़क दुष्प्रचारों से भी समाज को सचेत करना होगा, क्योंकि आज हकीकत से ज्यादा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर फर्जी फसाना फैलाने वाले साईबर साजिशों के गुरुघंताल काफी सक्रिय हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नकवी ने कहा कि कांग्रेस आजकल बिना शतक के शरारत की सनक में अपने को प्रेशर पम्प साबित करने की डींग मारने में जुटी है कि पप्पू के प्रेशर पम्प का कमाल है कि सरकार बैकफुट पर है, ऐसी खुशफहमी गलतफहमी साबित होगी। नकवी ने कहा कि कांग्रेस के गोदी गिरोह में खानदान अनेक, पर ख्वाहिशें एक हर सामन्ती सूरमा सत्ता की सूबेदारी के सपने में

सांप सीढ़ी के खेल में जुटा है, यही खेल यहां भी सामन्ती सुल्तान और समाजवादी टीपू के बीच चल रहा है। उन्होंने संसद में आए वकफ संशोधन विधेयक पर कहा कि वकफ व्यवस्था के असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना वकफ और वक्त की जरूरत है, जेपीसी में चल रहे मंथन से अमृत जरूर निकलेगा, इस संवैधानिक सुधार पर स्वार्थी वार ठीक नहीं है। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेहरू-इन्दिरा जी से ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और पंथनिरपेक्ष संकल्प के झंडाबरदार हैं, इसके लिए किसी सेकुलर सिन्डीकेट के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है, भारत के प्रजातंत्र की संवैधानिक ताकत को परिवार तंत्र की साम्प्रदायिक आफत से अपहरण नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अशफाक सैफी, अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी अध्यक्ष बासित अली एवं अन्य प्रमुख लोगों मौजूद रहे।

निःशुल्क मिलेंगी पॉपकॉर्न

बनाने की मशीनें, करे आवेदन

लखनऊ,। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत पिछड़े वर्ग के भुर्जी समाज के कारीगरों और पॉपकॉर्न उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। आधुनिक पॉपकॉर्न बनाने की मशीनें निःशुल्क वितरित की जाएंगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन कारीगरों को सहायता प्रदान करना है जो पारंपरिक तरीके से पॉपकॉर्न बनाने का कार्य करते हैं। लखनऊ जिले के कारीगरों जो पॉपकॉर्न उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में संलग्न हैं वो अपना आवेदन 5 सितंबर तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, 8 कैप्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

खेल प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स ने बढ़चढ़ कर लिया हिस्सा, विजयी प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित



लखनऊ,। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आलमबाग के कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में खेल उत्सव हुआ। प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। विजयी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय की

प्राचार्या प्रो. सारिका दुबे का कहना है कि खेल उत्सव में लेमन रेस, थ्री लेग रेस, स्लो साइकिलिंग रेस, सुई धागा रेस, बनाना रेस, हॉप रेस जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सर्वजन

हिताय संरक्षण समिति महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और समाज सेविका रीना त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी योगेंद्र चौधरी, सुमन और ललित प्रकाश पांडे भी आयोजन में मौजूद रहे। विजयी प्रतिभागी छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर मुख्य अतिथि रीना त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसे में सभी बच्चों को नित्य अपनी दिनचर्या में खेलों को शामिल करना चाहिए। बच्चों को फिटनेस से लेकर जीवन में जुड़े खेल के महत्व के बारे में भी जानना भी आवश्यक है। आयोजन के अंत में क्रीड़ा समिति की संयोजिका डॉ. मीनाक्षी त्रिपाठी और कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉ. सत्या शुक्ला ने कार्यक्रम में शामिल अतिथियों, शिक्षकों, छात्राओं समेत समस्त लोगों का आभार जताया।

प्रेमी ने खुदकुशी लिए था उकसाया, आरोपित गिरफ्तार



लखनऊ। महानगर कोतवाली पुलिस ने मार्शल आर्ट प्रशिक्षका को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले प्रेमी शिवम रावत को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रेमी शादी का झांसा देकर प्रशिक्षका का शारीरिक शोषण करता रहा। कई दिनों तक उत्पीड़न के बाद प्रेमी ने शादी से मना कर दिया। प्रेमी की करतूत से आहत प्रशिक्षका ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। प्रभारी निरीक्षक

अखिलेश मिश्र ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने रहीमनगर निवासी होटलकर्मी शिवम रावत पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती मार्शल आर्ट प्रशिक्षका से हुई थी। इसके बाद दोनों अक्सर फोन पर बातचीत करते आर साथ घूमने जाते थे।

कुछ ही देर में सोशल मीडिया में छा गया ओपीएस मुद्दा

लखनऊ,। केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के बाद यूपीएस योजना लाने के बाद कर्मचारी शिक्षक भड़क हुए हैं। सोशल मीडिया में एक्स पर एनपीएस और यूपीएस के विरोध में पूरा देश "नो एपीएस, यूपीएस ओनली ओपीएस टॉप ट्रेडिंग" में रहा। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि एनएमओपीएस के आह्वान पर पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनपीएस और यूपीएस हटाकर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिये ट्रेडिंग अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने बताया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की 27 अगस्त को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में मोदी सरकार द्वारा घोषित की गई यूनाइटेड पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए नो एपीएस, यूपीएस

ओनली ओपीएस हैशटैग ट्रेंड करारा गया। यह हैशटैग ट्रेडिंग में टॉप 380 हजार पर 20 मिनट में ही आ गया। कई घंटे लगातार ट्रेंडिंग में बना रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा एनपीएस की तरह यूपीएस भी कर्मचारियों के साथ छलावा है जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इसलिये सरकार एनपीएस, यूपीएस को समाप्त कर हुबहू पुरानी पेंशन बहाल करे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि एनपीएस, यूपीएस को रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल करें जिससे करोड़ों शिक्षकों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके। पत्र उन्होंने यूपीएस की तमाम खामियों को भी उजागर किया। डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि देश का शिक्षक व कर्मचारी यूपीएस से सहमत नहीं है।

समाधान किए गए मामलों में दोनों पक्षों की सहमति व गवाहों के करारे हस्ताक्षर-जिलाधिकारी



औरैया,। जिलाधिकारी डॉ॰ इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने मिशन समाधान के तहत सरकारी भूमि, चक्रोड तथा नालीकूल, शमशान सहित अन्य सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा किए गए अवैध कब्जा एवं आपसी विवादों को निस्तारित कराने के लिए तहसीलवार गठित राजस्व व पुलिस की

टीमों द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाहियों को तहसील औरैया के दिबियापुर व तहसील बिधूना के ग्राम नगला महातिया में स्वयं स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए संबंधितों को निर्देशित किया कि कब्जा मुक्ति व आपसी मामलों के निस्तारण को नियमानुसार व निष्पक्षता के साथ करते

हुए स्थाई समाधान सुनिश्चित करें, जिससे पुनः अवैध कब्जा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की फोटो वीडियो ग्राफी भी कराये और यदि निस्तारण के उपरांत किसी के द्वारा शांतिभंग अथवा कोई विवाद पैदा किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व लेखपाल को निर्देशित किया कि मिशन समाधान के अंतर्गत सतत प्रक्रिया संचालित रखते हुए सरकारी भूमि, चक्रोड, नालीकूल, शमशान, कृषि भूमि आदि के अवैध कब्जों के साथ-साथ आम जन के आपसी भूमि विवादों को भी नियमानुसार कार्यवाही करते हुए स्थाई समाधान करना सुनिश्चित करें।

जल बचाया जा सकता है, बनाया नहीं

लखनऊ,। राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जनपद बाराबंकी में जल बिरादरी व बिरजू संस्थान एवं जेबीएस इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में भूगर्भ जल बढ़ाने को लेकर चौमासे की बरसात विषयक संगोष्ठी एवं पर्यावरण रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पर्यावरणविदों ने कहा कि कल के लिए जल बचाना बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी, उत्तराखंड के पर्यावरणविद सुरेश भाई ने कहा कि जल बचाया जा सकता है, बनाया नहीं। कल के लिए जल बचाएं, जिसकी शुरुआत हिमालय से होनी चाहिए। हमारा रक्षक, जीवनदायी हिमालय ही खतरे में है। दिल्ली के पर्यावरण विद अरुण तिवारी ने कहा कि जन बढ़ रहे हैं और हमारा वन घट रहा है, वन घटने पर जल की भारी त्रासदी होने की संभावना है। गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रमेश शर्मा ने कहा कि प्रगतिशील समाज ने नदियों की धाराएं मोड़ दी, उनकी गोद में कंक्रीट बढ़ रहे हैं जो यह नदियां असमय सूख रही हैं वहीं बारिश में तबाही भी लाती हैं। अमेठी जल बिरादरी के अध्यक्ष पर्यावरणविद डॉ अर्जुन पांडेय ने कहा कि धरती की प्यास बुझाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़

लगाओ, पेड़ बचाओ। यही कृत्य मनुष्य जीवन को बचा सकता है। कार्यक्रम में संघ के जिला कार्यवाह सुधीर तिवारी ने चौमासे की खेती, चौमासे की बरसात को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। वहीं कई विश्वविद्यालयों में कुलसचिव



रहे प्रकृति प्रेमी पीएन प्रसाद ने छात्रों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य व उपायुक्त एस राम ने बताया कि धरती पर मात्र तीन प्रतिशत पानी पीने योग्य है, उसका दोहन रोकना होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ विनय दास ने कहा कि पर्यावरण व जल संकट से जन जीवन पर संकट बढ़ेगा, इसको

रोकना होगा। तिलोई डिग्री कालेज के प्रोफेसर डॉ अभिमन्यु पांडेय ने भी सम्बोधि त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जेबीएस इंस्टीट्यूट की प्रबन्धक पूनम सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। तथा कालेज में

छात्रों की जल साक्षरता इकाई को स्थापित करने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन बाराबंकी जल बिरादरी के संयोजक व बिरजू संस्थान के अध्यक्ष रत्नेश कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में जेबीएस इंस्टीट्यूट तिन्दुवानी के एचओडी सहदेव प्रसाद यादव व सभी प्रोफेसर फैकल्टी सहित बीएड, बीफार्मा डीफार्मा के लगभग 200 छात्र छात्राएं उपस्थित

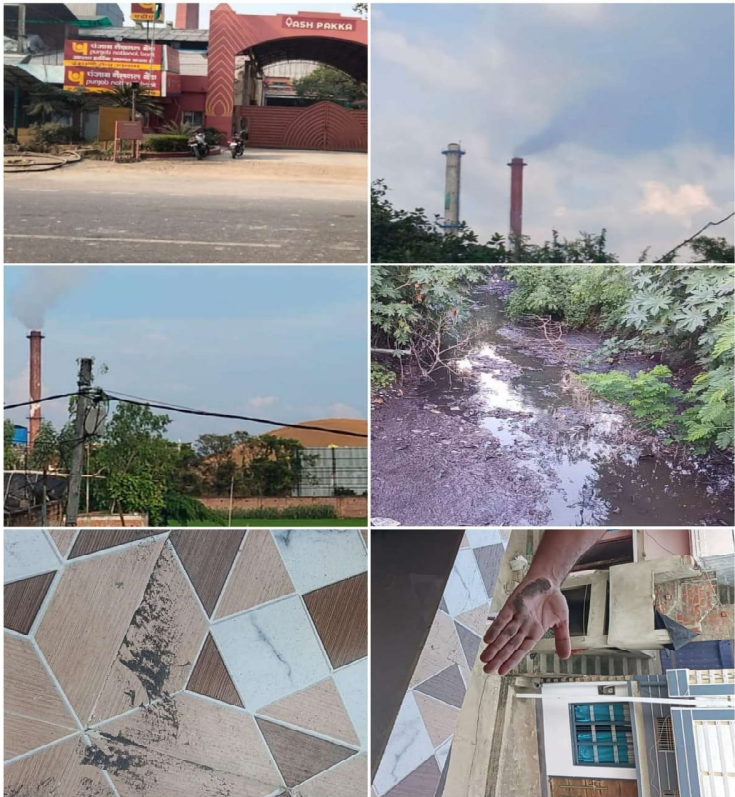
रही। जल साक्षरता अभियान के इस कार्यक्रम में पर्यावरणविदों के साथ बाराबंकी जिले के कई समाजसेवियों, प्रकृति प्रेमियों को सम्मानित किया गया। एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण अभियान में सक्रिय रहे साहित्यकार डॉ विनय दास, रेडक्रॉस के चेयरमैन शैलेंद्र सिंह, डॉ भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल सेवा समिति के महासचिव राम औतार, जे एल भास्कर, रमेश चौधरी, गुलजार बानो

व नितिन श्रीवास्तव, सतीश कश्यप, दिलीप श्रीवास्तव, पाटेश्वरी प्रसाद, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद कुमार, देव कुमार गुप्ता, पूर्व डीपीआरओ अनिल कुमार श्रीवास्तव, कवि सनत कुमार अनाड़ी सहित तीन दर्जन समाजसेवियों, प्रकृति प्रेमियों को पौधरोपण कार्य में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान पत्र अंगवस्त्र सम्मानित किया गया।

एसीएस परिवहन से निगम कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांगों को लेकर की मुलाकात

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर अपर मुख्य सचिव परिवहन से वार्ता की। परिवहन निगम एवं कर्मियों की समस्याओं के समाधान की मांग का ज्ञापन सौंपा। अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने मासूम अली सरवर प्रबंध निदेशक पवन निगम एवं मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन पर परीक्षणोपरांत आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। उन्होंने वार्ता के दौरान यह भी कहा कि परिवहन निगम प्रदेश के यात्रियों को बेहतर एवं आरामदायक सेवा देने के लिए कटिबद्ध है, और इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि मृतक आश्रितों की भर्ती का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। वहां से सम्यक निर्देश प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त हुई स कर्मचारी संगठन द्वारा प्रस्तावित आमरण अनशन भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

पेपर मिल का प्रदूषण बन रहा है लोगों के लिए काल



संवाददाता
अयोध्या। जनपद के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत दर्शन नगर पारा खान में स्थापित यस पेपर मिल की चिमनी से निकलने वाले प्रदूषण से आसपास की कई ग्राम सभाएं प्रभावित हो रही हैं जिसके चलते मानव, जीव जंतुओं के साथ-साथ किसानों की उपज भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेपर मिल की चिमनी से निकलने वाला धुआं अपने साथ-साथ राख व केमिकल उड़ता रहता है, पेपर मील से निकलने वाला दुर्गंध युक्त धुआं जहां लोगों को स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न कर रहा है वहीं जानवर भी प्रदूषण के चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं, चिमनी के धुएं के साथ उड़ने वाली राख से स्थानीय लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है तमाम लोग आंख रोगी हो चुके हैं तमाम लोगों को अपनी आंखों से पेपर मिल की उड़ती

राख निकलवाने के लिए नेत्र चिकित्सालयों का चक्कर लगाना पड़ता है मील के धुएं के साथ-साथ उड़ने वाली राख के चलते लोग बाहर अपना कपड़ा, अनाज आदि फैलाने से बचते हैं यहां तक स्थिति बनी है कि लोगों के घरों की दीवारों फर्सों पर मील की उड़ती राख का कुछ ही घंटे में लेयर बन जाता है य राख लोगों के श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच श्वास रोगी, दमा के रोग हो रहा है इसी के साथ ही मिल के धुआ के साथ बदबूदार केमिकल भी उड़ता है जिसके दुर्गंध से लोगों का जीवन जीना हराम हो रहा है मिल के चिमनी से निकलते धुएं के साथ उड़ रहा केमिकल फसलों के उत्पादन को प्रभावित करने के साथ-साथ मानव, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है इसी के साथ मिल से निकलने वाला दुर्गंध युक्त गंदा पानी ने

लोगों का जीना मुहाल कर रखा है स्थानीय लोगों के अनुसार मिल का गंदा पानी कच्चे नाले के सहारे पवित्र पावन सरयू नदी में जाता है जिसके चलते जहां भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो रहा है वही अयोध्या की पवित्र पावन सरयू नदी भी मैली हो रही है। पारा खान के पूर्व प्रधान समाजसेवी रामजनम मौर्य का कहना है कि पांच सौ लोगों को रोजगार देकर पचास हजार लोगों को जहर देने का काम यस पेपर मिल वाले कर रहे हैं यहां कृषि भूमि पर फैक्ट्री चल रही है यहां कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है इस फैक्ट्री से सभी प्रकार के प्रदूषण निकल रहा है चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो य ध्वनि प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषण हो रहा है। यह फैक्ट्री भूगर्भ जल का उपयोग कर पीने योग्य पानी का दोहन कर रही है जिसके कारण यहां का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है बारिश में भी तमाम बोरिंग पानी नहीं दे पा रही है। जो लोग इसकी शिकायत करते हैं उनको फैक्ट्री वाले बताते हैं कि यह लोग पैसे के लिए यह कर रहे हैं इसी प्रकार सभी को बदनाम करते हैं इसीलिए आवाज नहीं उठ पा रही है। हमने जिले के सभी अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के पास यस पेपर मिल से हो रहे वायु, जल, व ध्वनि प्रदूषण के बारे में अवगत कराया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फैक्ट्री का गंदा पानी रात में छोड़ा जाता है जो बिना फिल्टर गंदा दुर्गंधयुक्त पानी होता है, अधिकारियों द्वारा कहा जाता है की फैक्ट्री द्वारा फिल्टर किया हुआ स्वच्छ पानी छोड़ा जाता है लेकिन इसके विपरीत स्वच्छ अयोध्या पवन अयोध्या की पवित्र सरयु नदी को दूषित पानी छोड़कर प्रदूषण किया जा रहा है । इन्होंने यह भी चौलेंज किया कि फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी को कोई अधिकारी कर्मचारी 1 लीटर भी अपने कमरे में रात भर रख रह नहीं

सकता है। स्थानीय सेवक हरिप्रसाद यादव का कहना है कि यहां हजारों लोग पेपर मिल की वजह से परेशान हैं यहां पेपर मिल वाले बारिश के समय खास प्रकार के केमिकल उड़ाते हैं जिससे यहां बारिश बहुत कम होती है इस फैक्ट्री से निकलने वाली प्रदूषण की शिकायत जनपद ही नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री तक से किया जा चुका है। जो लोग जांच पड़ताल करने आते हैं वह बिक जाते हैं मिल से निकलने वाला गंदा पानी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। स्थानीय निवासी कन्हैया लाल यादव का कहना है कि पेपर मील की चिमनी से राख उड़ती है जिसके चलते हम सभी लोग परेशान हैं हमारे दो बच्चों की आंख में राख पड़ चुकी है जिसका हम इलाज करवा रहे हैं राख इतनी उड़ती है कि घरों के छतों,फर्स पर इकट्ठा हो जाती है। प्रदूषण से फसल का उत्पादन कम हो रहा है। हमारे बच्चे मील के ही स्कूल में पढ़ते हैं मिल की चिमनी से निकलने वाली राख की शिकायत हमने स्कूल में अध्यापकों से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी योगनाथ मौर्य ने बताया मिल की चिमनी से निकलने वाली राख से जहां आंख खराब हो रही है वही लोग दमा, श्वास रोगी हो रहे हैं। स्थानीय निवासी कमला देवी ने बताया कि मील से उड़ने वाली राख से हम लोग गेहूं अनाज आदि बाहर नहीं फैला सकते हैं तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। वहीं राम सजीवन यादव ने बताया कि राखी वह भूखी आदि हवा चलने पर उड़ती है जिसके चलते आंखें खराब हो रही है मेरी भी आंख इसी वजह से खराब हो रही है जिसका इलाज मैं फेको सेंटर से करा रहा हूं स्थानीय निवासी विदमा देवी ने बताया कि मिल का बहुत दुर्गंध युक्त पानी निकलता है जो विशेष तौर पर रात में छोड़ा जाता है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं होता है हम जिस हैंडपंप का पानी पीते हैं उसमें भी इस दुर्गंध का

झाग आता है बच्चों की तबीयत खराब हो रही है नात- रिश्तेदार बदबू की वजह से भाग जाते हैं । इसकी जांच पड़ताल करने तमाम लोग आते हैं रहते हैं कैमरा से फोटो आदि बनाकर चले जाते हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है धुएं की राख की वजह से फसल प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासी रामसागर का कहना है कि हवा चलने मील से निकल प्रदूषण से कपड़ा खाना पीना सभी प्रभावित हो रहा है तमाम जानवरों को भी प्रदूषण के चलते त्वचा रोग हो रहा है हमारी पत्नी की आंख में मिल की राख पड़ चुकी है जिसे मैं इलाज कर रहा हूं। यस पेपर मिल के प्रदूषण को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह ने कहा मेरा घर भी वही है मैं बचपन से देख रहा हूं कि वह मिल वहीं पर स्थापित है। अयोध्या गरिमा के अनुरूप जिस तरह विकास हो रहा है मुझे लगता है की आबादी के बीच से मील को हटा देना चाहिए अगर नहीं हटाया जाता है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आमजन को समस्या न हो प्रदूषण की समस्या के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए जिले से प्रदेश तक समस्या गई है मील और किसानों के बीच कई बार संघर्ष हुआ है। पेपर मील बड़े व्यक्ति की है जो दबंग है निश्चित ही कभी-कभी किसान पिस जाते हैं लेकिन हम सबका प्रयास रहता है कि किसानों की जमीन जो उसर हो रही है मिल के नाले का पानी इधर-उधर जाता है उसको फिल्टर करके छोड़ जाए जो नाले के सहारे ही जाए जिससे कि वह पानी किसानों के उपयोग में आ सके मैं मिल से कहना चाहूंगा कि मिल से जो राख व केमिकल उड़ रहा है उसके लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए अगर उसका दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार व केंद्र में नरेंद्र मोदी की प्रदेश सरकार है किसी को बक्सा नहीं जाएगा।

प्रापर्टी कारोबारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या,मचा कोहराम

लखनऊ। लखनऊ में प्रापर्टी कारोबार में पार्टनर के धोखा देने के बाद लाखों की रकम डूबने के चलते डिप्रेशन में आये प्रापर्टी कारोबारी ने गुरुवार की सुबह मोहनलालगंज के बैरीसालपुर में किराये के मकान के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक कारोबारी के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिये भेजा। लखनऊ के इन्दिरानगर निवासी प्रापर्टी कारोबारी अजय शर्मा(14वर्ष) अपनी पत्नी दीपिका शर्मा व बेटे आदित्य,बेटी अदिति के साथ मोहनलालगंज के बैरीसालपुर में अपनी ससुराल के पास बीते कुछ वर्षों से एक मकान किराये पर लेकर रहते थे। पत्नी दीपिका ने बताया बीते बुद्धवार को खाना खाने के बाद पति अपने कमरे में सोने चले गये और वो बच्चों के साथ सो गयी,जिसके बाद कारोबारी अजय ने कमरा अंदर से बंदकर छत में लगे पंखे के हुक में गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।गुरुवार की

सुबह बच्चों के स्कूल जाने की ड्रेस लेने के लिये पति के कमरे में गयी तो कमरे का दरवाजा अंदर से लांक था काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला जाली से अंदर झांक कर देखा तो अंदर छत में लगे पंखे के हुक में गमछे के सहारे पति का शव लटका रहा था,जिसके बाद इसके होश उड़ गये और कोहराम मच गया।मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने घटना की सूचना मोहनलालगंज पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक प्रापर्टी कारोबारी के शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा। इस्पेक्टर आलोक राव ने बताया प्रथम दृष्टया जांच में प्रापर्टी कारोबार में लाखों की रकम डूबने के चलते कारोबारी अजय शर्मा डिप्रेशन में आ गये थे जिसके चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है,पीएम में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी। परिजनों ने बताया अजय शर्मा

का इंदिरानगर में प्रापर्टी का काम था कुछ साल पहले तक उसका काम भी ठीक चल रहा था लेकिन कारोबार में पार्टनर के धोखा देने के बाद उसका 45लाख रुपये डूब गया था जिसके बाद से अजय डिप्रेशन में आ गया था और लखनऊ छोड़कर मोहनलालगंज के बैरीसालपुर में अपनी ससुराल के पास एक किराये का मकान लेकर परिवार समेत रह रहा था।लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था।पत्नी ने एक ओर प्रापर्टी डीलर पर पति का कई लाख रुपये डकारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया मृतक अजय शर्मा के पिता राम नारायण शर्मा ने इंदिरानगर क्षेत्र में अपनी एक जमीन बेचा था जिसमें पिता को काफी पैसा मिला था और अजय के हिस्से में 50लाख आया था,पिता से मिली रकम से उसने प्रापर्टी कारोबार में लगाकर पार्टनर के साथ काम शुरू किया था लेकिन पार्टनर के धोखा देने के बाद उसकी रकम डूब गयी थी और वो डिप्रेशन में चला गया था।

छात्रा ने वृद्ध पर लगाया छेड़खानी का आरोप

लखनऊ,।

आलमबाग कोतवाली अंतर्गत ई-रिक्शा में सवार होकर कोचिंग से घर लौट रही छात्रा ने बगल में बैठे बुजुर्ग (60) पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि बुजुर्ग ने उससे अश्लील हरकत की। इस पर उसने विरोध किया तो ई-रिक्शा में सवार लोग तमाशबीन बने रहे। इस बीच ई-रिक्शा चालक छात्रा की मदद करने के बजाए बुजुर्ग को लेकर चला गया। छात्रा का कहना है कि छेड़खानी की वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि, पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मूलरूप से सिद्धार्थनगर जनपद की रहने वाली छात्रा (20) छोटी बहन के साथ सरोजनीनगर के स्कूटर इंडिया में किराए के मकान में रहती है। लिखित शिकायत में छात्रा ने बताया कि वह ऐशबाग के एक कॉलेज में जीएसएम की तैयारी कर रही हैं। छात्रा का

कहना है कि बुधवार सुबह करीब पौने बारह बजे वह कोचिंग से घर पर जाने के लिए ऐशबाग से ई-रिक्शा पर सवार हो गई। उसका आरोप हैकि ई-रिक्शे के सामने की सीट पर दो युवक बैठे थे, वहीं उसके बगल में करीब 60 वर्षीय शख्स बैठा था। छात्रा का कहना है कि मवैया ओवर ब्रिज क्रॉस होते ही बुजुर्ग उससे गलत हरकत करने लगा। इस पर छात्रा शोर मचाने लगी, तो आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। छात्रा का कहना है कि उसके साथ जहां घटना हुई उसके ठीक सामने पुलिस बूथ भी है, लेकिन उस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। आरोप है कि इस बीच ई-रिक्शा चालक किराया लेने की बात कहकर बुजुर्ग को लेकर चला गया। इसके बाद छात्रा ने आलमबाग कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक एसएन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

